

मुख्यमंत्री ने जनपद कुशीनगर में नारायणी नदी के ए०पी० तटबंध टूटने से बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया

बांध कटान स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री किट व लंच पैकेट वितरित किये

राहत सहायता, बचाव कार्य, स्वास्थ्य, आवास, फसल क्षति तथा तटबंध की सुरक्षा से जुड़े कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी : मुख्यमंत्री

राहत एवं बचाव के लिए एन०डी०आर०एफ० व एस०डी०आर०एफ० की ०२-०२ टीमें और पी०ए०सी० की फ्लड यूनिट तैनात की गई

जनहानि होने पर ०४ लाख रु० की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश

जिस परिवार का मकान पूरी तरह नष्ट, उसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' या 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत नया आवास उपलब्ध कराया जाए, जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त और मरम्मत सम्भव, उन्हें मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए

फसल क्षति का सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को अगले १० दिन में मुआवजा उपलब्ध कराया जाए

सम्पूर्ण तटबंध को इस प्रकार मजबूत किया जाए कि आने वाले समय में फिर कभी उसके टूटने की स्थिति न आए और क्षेत्र को नुकसान से बचाया जा सके, नदी को ड्रेजिंग करके चैनलाइज किया जाना चाहिए

प्रभावित क्षेत्र में अगले ०५ से ०६ दिनों तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं, बाढ़ के बाद जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए

जिन गांवों में पानी आ गया और जिनके घर टूट गए, प्रशासन उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में ले जाए, राहत शिविरों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

लखनऊ : २९ सितम्बर, २०२६

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जनपद कुशीनगर में नारायणी नदी के ए०पी० तटबंध टूटने से बाढ़ की त्रासदी से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बांध कटान स्थल का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री किट व लंच पैकेट वितरित किये। उन्होंने सामग्री वितरण स्थल पर बाढ़ प्रभावितों से संवाद किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि काफी वर्षों के उपरान्त इस प्रकार की बाढ़ की स्थिति आयी है। नेपाल से अचानक अधिक पानी आने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उम्मीद है कि शीघ्र ही इसमें राहत मिलेगी। आपदा की इस घड़ी में पूरी सरकार

प्रभावित लोगों के साथ है। प्रशासन हर सम्भव सहायता के लिए उनके साथ खड़ा है। जनप्रतिनिधि भी प्रभावित क्षेत्रों में रहकर सहयोग कर रहे हैं। राहत सहायता, बचाव कार्य, स्वास्थ्य, आवास, फसल क्षति तथा तटबंध की सुरक्षा से जुड़े कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

लगातार चार दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि की भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा। नेपाल में अतिवृष्टि के कारण बड़ी मात्रा में जमा पानी अब नीचे की ओर आ रहा है। सामान्य दिनों में नारायणी नदी में 03 से 04 लाख क्यूसेक पानी का प्रवाह होता था, लेकिन बाढ़ के दिनों में अचानक यह बढ़कर साढ़े पांच लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। इसके कारण ए0पी0 तटबंध टूट गया और कई गांवों में पानी पहुंच गया।

प्रशासन कल से ही स्थिति पर नजर रखे हुए था। राहत एवं बचाव के लिए एन0डी0आर0एफ0 की 02 टीमों, एस0डी0आर0एफ0 की 02 टीमों और पी0ए0सी0 की फ्लड यूनिट तैनात की गई है। सम्पूर्ण जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के सभी अभियन्ता राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ए0पी0 तटबंध टूटने की जानकारी मिलते ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया है। पीड़ित परिवारों के लिए राहत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। राहत दल मौके पर कार्य कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री के 5,000 पैकेट उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक पैकेट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 02 किलो दाल, लाई, चना, तेल, मसाले, नमक, बाल्टी सहित 35 आइटम्स हैं। प्रत्येक पैकेट का कुल वजन लगभग 50 किलो है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को सहायता देने का निर्णय लिया है। यदि कहीं जनहानि हुई है तो आपदा की श्रेणी में सम्बन्धित परिवार को तत्काल धनराशि उपलब्ध कराई जाए। जनहानि होने पर 04 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस परिवार का मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है, उसे 'प्रधानमंत्री आवास योजना' या 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत नया आवास उपलब्ध कराया जाए। जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और जिनकी मरम्मत सम्भव है, उन्हें मरम्मत के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

15-16 गांवों में बड़े पैमाने पर फसल, खासतौर पर धान, गन्ना तथा सब्जी की फसल प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि फसल क्षति का सर्वे कराकर पीड़ित किसानों को अगले 10 दिन में मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। इसमें किसी प्रकार की देरी न की जाए। बाढ़ के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत

कराई जाए। उन्होंने कहा कि तटबंध टूटने के बाद सिंचाई विभाग की पूरी टीम को निर्देश दिया गया है कि सम्पूर्ण तटबंध को इस प्रकार मजबूत किया जाए कि आने वाले समय में फिर कभी उसके टूटने की स्थिति न आए और क्षेत्र को नुकसान से बचाया जा सके।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में अगले 05 से 06 दिनों तक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएं। बाढ़ के बाद जलजनित विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को प्रत्येक प्रकार की आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एण्टी-स्नेक वेनम और एण्टी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध रहे। किसी व्यक्ति के सामने ऐसी संकट की स्थिति आने पर उसे वैक्सीन के लिए इंतजार न करना पड़े तथा उसकी जान बचाई जा सके। प्रत्येक व्यक्ति की जान सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।

जिन गांवों में पानी आ गया है और जिनके घर टूट गए हैं, प्रशासन उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में ले जाए। राहत शिविरों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाए। बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि बिजली नहीं है, तो जनरेटर की व्यवस्था से प्रकाश पहुंचाया जाए, ताकि प्रभावित लोगों को अंधेरे की स्थिति का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्तमान स्थिति से निपटने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी स्थायी समाधान पर कार्य किया जाए। यदि सम्भव हो तो नारायणी नदी को ड्रेजिंग करके चैनलाइज किया जाना चाहिए। नदी में जो सिल्ट है, उसे दोनों तरफ डाल दिया जाए। इससे किसानों के खेतों को भी नुकसान नहीं होगा और नदी चैनलाइज हो जाएगी। नदी गहरी होने के बाद आगे अपनी राह स्वयं बना लेगी और सम्पूर्ण क्षेत्र भविष्य के लिए सुरक्षित हो सकेगा।

इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह, सांसद श्री शशांक मणि व श्री विजय कुमार दूबे, विधायक डॉ० असीम कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।